सच्चे लोगों को कभी प्रसंशा की आवश्यकता नहीं होती जैसे फुलों को इत्र की जरूरत नहीं होती।
– अज्ञात

श्रम सुधारों का रास्ता

लेबर कानूनों की सख्ती के कारण ही कई उद्यमियों ने दूसरे देशों का रुख किया। बहुतों ने तो कारोबार डूबने के डर से उद्यम लगाने ही बंद कर दिए। सचाई यह है कि केंद्र और राज्यों के करीब 200 कानूनों की वजह से आज मजदूर दर-दर भटक रहे हैं।

मनोज झा।

कोरोना वायरस की वजह से बेजान पड़ी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए देश में श्रम सुधारों का रास्ता अपनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राज्य सरकारों की तरफ से हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने इस संबंध में पहलकदमी की और फिर असम, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा ने भी इस दिशा में कुछ अहम फैसले किए, जिनका दूरगामी असर हो सकता है।

बिहार और कुछ अन्य राज्य भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार करने को लेकर जो अध्यादेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि राज्य में अगले तीन सालों के लिए 35 बड़े श्रम कानून लागू नहीं किए जाएंगे। हालांकि, महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून अभी बने रहेंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने कुटीर उद्योगों और छोटे कारोबारों को रोजगार, रजिस्ट्रेशन और जांच से जुड़े विभिन्न जटिल श्रम नियमों से छुटकारा देने की पहल की है, साथ ही कारखानों और कार्यालयों में काम कराने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। हफ्ते में 72 घंटे तक कार्य कराए जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए श्रमिकों को ओवर टाइम देना होगा।

असम सरकार ने भी काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए हैं। उसने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट नीति अपनाई है। कंपनियां अब ठेकेदारों की मदद लेने के बजाय सीधे निश्चित अवधि के लिए श्रमिकों की नियुक्ति कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अन्य मजदूरों की तरह तमाम सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती दरअसल कोरोना के प्रकोप से पहले ही आने लगी थी और कई विशेषज्ञों की राय थी कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म करने होंगे।

मजदूरों से जुड़े मौजूदा कानूनों में से कई इंदिरा गांधी के दौर में बनाए या संशोधित किए गए थे, लेकिन व्यवहार में उनका विपरीत असर पड़ा। इनसे लाइसेंस राज को बढ़ावा मिला, जिसने उद्यमियों के लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कीं। लेबर कानूनों की सख्ती के कारण ही कई उद्यमियों ने दूसरे देशों का रुख किया। बहुतों ने तो कारोबार डूबने के डर से उद्यम लगाने ही बंद कर दिए। सचाई यह है कि केंद्र और राज्यों के करीब 200 कानूनों की वजह से आज मजदूर दर–दर भटक रहे हैं। ये कानून कागज पर भले ही कामगारों के हितों की रक्षा करते दिखते हैं, पर वास्तव में ये संगठित क्षेत्र में उनके रोजगार की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं।

यही वजह है कि आज 90 फीसदी रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं। इन्हीं की वजह से भारत के ज्यादातर उद्मम छोटे से बड़े नहीं हो पाते। बहरहाल, अब राज्यों की पहल से माहौल बदलेगा। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि बड़े पैमाने पर निवेश हो, उद्योग–धंधे शुरू हों और लोगों को रोजगार मिले।

उम्मीद है कि इन उपायों से राज्यों को तो लाभ होगा ही, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।

शब्दों का महत्व

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। अपनों से दो मीठे बोल और तारीफ के शब्दों का महत्व भी समझो। आरोग्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पारिवारिक प्रसन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा के सूत्र भी सुखी जीवन जीने के लिए गुणसूत्र हैं। 'मामुपाश्रिता' मेरे अंदर जो अपने आपे को अर्पित कर चुके हैं वे लोग ज्ञान और तप के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गये हैं, मेरे धाम तक पहुँच गये हैं। आइए! हम सब न केवल प्रभु का मानें, बल्कि प्रभु को भी मानें। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हर व्यक्ति एक अलग आत्मा है और उनका अपना भविष्य है। इसी तरह हमारे बच्चे को रचयिता के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना और समर्थन देना, भावनाओं का एक नाजुक संयोजन है। इसलिये उनके जीवन के सभी पहलुओं के विकास के लिए बच्चों को मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बात करने की अनुमति देना जरूरी है।

संपादकीय

जागरूकता ही मंत्र

महामारी नियंत्रण के पिछले अनुभव बताते हैं कि सामुदायिक स्तर की जागरूकता बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। इससे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाएं देना आसान हो जाता है। सरकार को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के प्रभावी उपयोग के साथ आईईसी (इनफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्यूनिकेशन) गतिविधियां भी जारी रखनी चाहिए। आईईसी के माध्यम से सामुदायिक सशक्तीकरण, जागरूकता और बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन इस महामारी के प्रबंधन की आधारशिला साबित होंगे।

प्रभावी नेतृत्व संकट को भारी बनाने की बजाय व्यवस्थित दृष्टिकोण से उसका प्रबंधन कर सकता है। केंद्रीकृत निगरानी और कठोर दंड लोगों से लाभकारी दिशा–निर्देशों का पालन कराने का एकमात्र तरीका नहीं है। जब लोगों को वैज्ञानिक तथ्य बताए जाते हैं, उचित समय पर ठोस कदमों की सूचना दी जाती है तो आमजन में भरोसा बढ़ता है। स्व–प्रेरित और सही सूचनाओं से लैस आबादी सरकार नियंत्रित, अज्ञानी आबादी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती है। आज लाखों भारतीय रोजाना हाथ धोते हैं। इसलिए नहीं कि वे निगरानी से डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे यह बात समझते हैं कि बार–बार हाथ धोकर बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।

कोरोना महामारी भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार का बड़ा अवसर है। वर्षों से सामाजिक लक्ष्यों और स्वास्थ्य पर कम निवेश के कारण हम कई स्तरों पर महामारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आगे हमें स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए अधिक निवेश को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

लॉकडाउन से अकाल जैसी स्थितियां और कानून–व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो बाकी बातों के अलावा महामारी नियंत्रण के उद्देश्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी।

पर्याप्त टेस्टिंग नहीं

डॉ. महावीर गोलेच्छा।

लॉकडाउन महामारी के संक्रमण को रोकने का सबसे ठोस और आसान उपाय है, लेकिन लंबा लॉकडाउन अर्थतंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। अप्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों, बेरोजगारों और किसानों के लिए यह बहुत ही कठोर हालात पैदा कर देता है। हमें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि लंबे चलने वाले कड़े लॉकडाउन से अकाल जैसी स्थितियां और कानून–व्यवस्था से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो बाकी बातों के अलावा महामारी नियंत्रण के उद्देश्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगी। हमें दक्षिण कोरिया, जापान, स्वीडन, ताइवान, हांगकांग और चेक गणराज्य जैसे देशों से सीखने की जरूरत है कि कैसे इन देशों ने अपने यहां अर्थव्यवस्था को बचाते हुए महामारी को नियंत्रित किया।

निश्चित रूप से लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण काफी कम हुआ है, लेकिन याद रखना चाहिए कि देश में पर्याप्त टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है और अधिक केस न आने का यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ज्यादा संख्या में और तेज गति से टेस्टिंग कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। सरकार को सिरोलॉजिकल टेस्टिंग (रक्त नमूनों पर

आधारित टेस्टिंग) का सहारा लेना चाहिए। इससे हम बहुत कम समय में लाखों टेस्ट कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट पाए गए हैं, वहां पर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग काफी उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन सरकार को उन क्षेत्रों में भी टेस्टिंग करने की जरूरत है, जहां अभी तक पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। इससे हमें कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी मिलेगी।

ऐसे क्षेत्रों के लिए पूल्ड टेस्टिंग का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक टेस्ट किट द्वारा कई नमूनों का टेस्ट होता है। यदि संयुक्त नमूना पॉजिटिव निकला तो नमूनों को व्यक्तिगत रूप से टेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर पूल्ड टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके सारे सैंपल नेगेटिव मान लिए जाते हैं। कोरोना के प्रभावों के आरंभिक आकलन के लिए सरकार ने रोग से होने वाली मौतों व पुष्ट हो चुके मामलों की संख्या और उनके अनुपात का विश्लेषण करने पर ध्यान लगाया है। इस अनुपात को केस फेटैलिटी रेट (सीएफआर) कहा जाता है। लेकिन भारत जैसे देशों में सीएफआर बहुत विश्वसनीय नहीं माने जाते क्योंकि यहां मृत्यु पंजीकरण प्रणाली अधूरी और अपर्याप्त है। यहां अधिकांश मौतों में मेडिकल प्रफेशनल मृत्यु का कारण नहीं बताते हैं।

ऐसे में कोरोना के मामले में भी मृत्यु के वास्तविक आंकड़े शायद सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार को मृत्यु के वास्तविक आंकड़ों के लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए। कोरोना के नियंत्रण में काफी स्तरों पर केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय की कमी दिखी है। काफी राज्यों ने टेस्टिंग किट की कमी और निजी सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को लेकर अलग–अलग राज्यों ने भिन्न रणनीति अपनाई। यदि केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, आवास और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की होती तो ये मजदूर अपने राज्यों–गांवों की ओर पलायन के लिए मजबूर न हुए होते। इससे न केवल इन मजदूरों को परेशानी हुई बल्कि लॉकडाउन खुलने के बाद बड़े–बड़े उद्योगों को चलाने की समस्या भी खड़ी हो गई है।

सूडोकु नवताल-5354

	9				6			
	1					2		
5			7				3	
			4					6
		3				9		
4					8			
	7				9			8
		2					1	
			3				4	

सूडोकु नवताल -5353 का हल

6	5	8	9	1	4	2	7	3
1	2	7	3	5	8	6	4	9
3	4	9	7	2	6	1	5	8
2	3	6	1	4	5	9	8	7
8	9	5	2	7	3	4	1	6
4	7	1	6	8	9	3	2	5
7	6	4	5	3	1	8	9	2
9	8	2	4	6	7	5	3	1
5	1	3	8	9	2	7	6	4

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

अपना ब्लॉग

अगला हॉटस्पॉट

मोहन। जिस प्रकार प्रवासी मजदूर रेड जोन हॉटस्पॉट वाले शहरों से गांवों में गए हैं, शायद इस महामारी का अगला हॉटस्पॉट हमारे गांव ही हो जाएं। ऐसे में सरकार को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम शुरू करे। स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित करनी चाहिए। कोरोना प्रसार रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन भारतीय सामाजिक संदर्भ में आम नागरिकों के लिए यह मुश्किल होता है। ज्यादातर राज्यों में कई ऐसे समुदाय भी हैं जिनके पास बार–बार हाथ धोने के लिए पानी की उचित सुविधा नहीं है। कॉरपोरेट सीएसआर के सहयोग से ये सुविधाएं इन क्षेत्रों में दी जा सकती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थापित ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता समिति तथा रोगी कल्याण समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ धोने के संसाधन, साबुन, सैनिटाइजर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।